WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Strict enforcement of Hindu Seccession Act

*645. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
SHRI MISA R. GANESAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the share allotted to women in the Hindu Succession Act remains on the statute book but it is not being fully implemented!

(b) whether Government would call for a report from State Governments in respect of cases pending for shares for women in their joint family properties;

(c) what action Government propose to take to strictly enforce to apportion the shares to women; and

(d) whether Government would legislate for punishing the law-breakers in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The Hindu Succession Act, 1956 seeks to amend and codify the law relating to inter-state succession among Hindus. The rules of succession are laid down therein. The individual beneficiaries are at liberty to take advantage of the provisions of the Act. In case they feel aggrieved, they are at liberty to agitate the matter before the appropriate forum and seek remedy in accordance with the law.

(b) There is no specific method by which the statistics relating to pendency of cases relating to shares for women in the joint family properties alone could be collected.

(c) Since it is for the individual beneficiaries to take advantage of the rights available unler the Act. no action on the part of the Government is called for.

(d) No such proposal is under consideration.

Revival plans for HFC & FCI

*646. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(t) whether it is a fact that Governmen have failed as a promoter to submit any revival scheme for HFC and FCI to BIFR inspite of directives from the Bench after the Companies were referred to BIFR in November, 1992;

(b) if so, what are the reasons for the failure of the Department of Fertilizers to give such schemes when they are alretdy having a number of revival proposals for consideration, including proposal from Indian and foreign consultants, Trade Unions, Associations, etc.; and

(c) whether Government have any plans for the revial of HFC and FCI?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The Goernment was in the process of finalising the revival package after considering the various alternatives, including proposals from Unions/Officers' Associations as also the report of the consultants. However, during the last hearing on 30th/31st Deyember, 1993 for Hindustan Fertilizer Corporation Limited/Fertilizer Corporation of India Limited, the Board for Industrial and Financial Reconstruction (GIFH) directed to hold consultantions with the Workers' Unions Officers' Associations. Banks and the State Governments to arrive at an agreed revival package. The consultations with Unions/Officers' Associations, State Governments, and Banks took further time.

In the mean'ime, BIFR has appointed the Indusrial Credit and Investment Corportion of India Limited (ICICI) as the Operating Agency on 16-3-1994, directing the Government to submit the unit wise revival package to ICICI which in turn would submit a rehabilitation plan to BIFR. Any decision on the revival of these companies would depend on the outcome of the proceedings pending before the BIFR which is a quasi-judicial authority.

हिमाचल प्रदेश में भूकम्प वेधशालाओं का बंद किया जाना

*647. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार भूकम्प वेधशालायें कहां-कहां कार्यरत हैं और वे कब-कब से कार्यरत हैं –

(ख) इन वेधशालाओं के खोलने का औचित्य क्या था और वे वेधशालायें क्या-क्या कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को भूकम्पीय क्षेत्र माना जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू तथा धर्मशाला की भूकम्पीय वेधशालाओं को किन-किन कारणों से बन्द कर दिया गया है और निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में स्थित ऐसी छः अन्य वेधशालाओं को बन्द करने का निर्णय किन कारणों से लिया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभागों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) :

(क) भारत मौसम विज्ञान विभाग देश में अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में 37 भकम्पीय वेधशालायें चला रहा है। कलकत्ता के अलीपुर में पहली वेधशाला की सन 1898 मे स्थापना से लेकर आज तक इस नेटवर्क का धीरे-धीरे विस्तार किया जिसमें सबसे नवीन स्थापना 1993 में लातूर में की गई ! इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने भूकम्पीयता कार्यक्रम के यहत उत्तर पश्चिमी हिमाचल में 39 वेधशालाय स्थापिमे की जिनमें हिमाचल प्रदेश की 12 वेधशालायें शामिल हैं जिनकी स्थापना सन 1984 से शुरू की गई। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं दक्कन के पठार में भूकम्पीय केन्द्र चलाते हैं।

(ख) ये वेधशालायें भारत तथा इसके आस-पास के इलाकों की भूकम्पीय गतिविधियों की मानीटरिंग करती हैं। इन वेधशालाओं द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनका प्रयोग विभिन्न वैज्ञानिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में किया जाता है।

(ग) जी, हां, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाडियों, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्य वैसे ज्ञात भूकम्पीय जोनों में स्थित हैं जैसा कि ब्युरो आफ इंडियन स्टैंडर्स के जोनिंग मैप 15: 1993–94 में दिखाया गया है।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी कोई वेधशाला बन्द नहीं की है। कुल्लू तथा धर्मशाला स्थित वेधशालाएं जिन्हें भारत मौसम विभाग भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से संचालित करता है, बोर्ड के विशेष आग्रह पर बन्द कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश की 6 अन्य वेधशालाओं को बन्द करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। बोर्ड के कुल्लू तथा धर्मशाला स्थित वेधशालाओं के बन्द होने की वजह से